फैक्स: 05644 -260565, 260419M: 9549157392
ईमेलःashok.drmr@gmail.com

भा.कृ.अनु.प.–सरसों अनुसंधान निदेशालय

सेवर, भरतपुर (राजस्थान) 321 303

डॉ. अशोक कुमार शर्मा
प्रधानवैज्ञानिक एवं जनसम्पर्क अधिकारी

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 5.08.2020

देश में खाद्य तेलों की पूर्ति करने के लिए तिलहन का उत्पादन बढाना होगा– डॉ. त्रिलोचन महापात्रा

अखिल भारतीय राई–सरसों अनुसंधान परियोजना की 27 वीं कार्यशाला का आयोजन

तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए देश में खाद्य तेलों की पूर्ति करने के लिए तिलहन का उत्पादन बढाना होगा। राई सरसों का विकास एवं क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढ़ाना वैज्ञानिकों एवं किसानों का लक्ष्य होना चाहिए। वैज्ञानिको द्वारा कई किस्मों का विकास किया गया है लेकिन किसानो के खेतों पर उनकी उत्पादकता में काफी अनिश्चितता पाई जाती है। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में विकसित किस्मों एवं तकनीकों की टिकाउ उत्पादकता को बढाने की आवश्यकता है। यह बात डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सरसों अनुसधांन निदेशालय द्वारा 3–4 अगस्त 2020 को आयोजित अखिल भारतीय राई–सरसों अनुसंधान परियोजना की 27 वीं ऑनलाइन कार्यशाला में देश में कार्यरत राई–सरसों वैज्ञानिकोंको सम्बोधित करते हुये कही।उन्होनें कहा कि जबतक विकसित तकनीकें किसानों तक नही पहुँचेगीं और किसान उन तकनीकों को नही अपनायेगें तब तक कृषि अनुसंधान का उद्देश्य पूरा नही होगा। उन्होनें वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि विकसित किस्मों एवं तकनीकों के बारे में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलायें और विकसित तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। वैज्ञानिक किसानों के साथ नियमित संवाद की व्यवस्था कायम करें। किसानों के खेतों में विकसित तकनीकों एवं किस्मों का प्रदर्शन करें, उनकी फीडबैक प्राप्त करे और अनुसंधान की दिशा उसी तरह तैयार करें।डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि किसानो के विकास एवं उनकी आमदनी दुगुनी करने के लिए गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता एवं आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सही अनुसंधान तकनीकों को सही समय पर किसानों तक पहुँचाने के लिए सभी विभागों को मिलकर अग्रिम रणनीति बनानी चाहिए। उन्होने राई–सरसों के उत्पादन एवं विकास के लिए राज्यवार, जिलावार कृषि रणनीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), डॉ. तिलक राज शर्मा ने कहा कि नई किस्मों के विकास के लिये समेकित पादप तकनीकियों का समावेशी उपयोग किया जाना चाहिए। उत्पादकता में मौसम एवं तकनिकियों के योगदान का विश्लेषण वैज्ञानिको को करना चाहिए ताकि तकनिकियों के विकास एवं उनके हस्तान्तरण के लिये उपयुक्त रणनीति बनाई जा सकें। उन्होने वैज्ञानिकों से कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उच्च तापमान सहनशील, सूखा सहनशील, आदि किस्मों के विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करें। जलवायु परिवर्तन के कारण कई

नई समस्यायें कृषि में आ रही है। नई चुनौतियों के अनुसार अनुसंधान किया जाना चाहिये। आई पी एम तकनीको का पुनर्मुल्यांकन किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन), डॉ. एस. के. झा ने कहा कि राई–सरसों की उत्पादकता को मुख्य रूप से अनिश्चित वर्षा, पाला, उच्च तापमान, कीट एवं रोग का प्रकोप प्रभावित करते है। इनसे बचाव के लिये समुचित प्रबन्धन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। किसानो का उत्पादन बढाने के लिये सम्पूर्ण तकनिकियो के प्रदर्शन लगाये जाने चाहिए। उन्होने कहा कि तकनीको के विकास के साथ–साथ उनका किसानो तक पहुंचना भी जरूरी है इसलिए वैज्ञानिको ंको प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का सही तरीके से आयोजन करना चाहिए। गुणवत्ता युक्त बीजो की उपलब्धता बढाने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिए।

इस अवसर पर सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. पी.के. राय ने तोरिया, राई एवं सरसों फसल कि अखिल भारतीय परियोजना कि 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।डॉ. राय ने कहा कि फसल सुधार, सही प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं एवं अच्छे समर्थन मूल्यों से ही देश में तिलहन उत्पादन को बढाया जा सकता है। बदलते परिवेश में अधिक उत्पादन के लिये किसानो को जागरूक व प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आर्थिक सृदृढता के लिये किसानों को राई–सरसों की खेती को बढावा देने की जरूरत है। उन्होने बताया कि विभिन्न राज्यों में फैले हुए अनुसंधान केन्द्रो द्धारा तोरिया, पीली सरसों, गोभी सरसों, भारतीय राई, करन राई एवं तारामीरा की किस्मो के विकास का कार्य किया जा रहा हैं। इस वर्ष उन्नत किस्मों का प्रजनक बीज अधिक उत्पादन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप उन्नत किस्मों का व्यापक प्रसार हो सकेगा एवं देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रता मिल सकेगी। डॉ. राय ने जानकारी दी कि गत वर्ष देश भर में 26 केन्द्रों द्वारा 15 राज्यों के 57 जिलों में 1405 प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 125 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के लिए वहाँ की जलवायु, भूमि, संसाधन आदि स्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ राई–सरसों के उत्पादन को बढाने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस संगोष्ठी में प्रजनक बीज उत्पादन, तकनीकि हस्तांतरण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन एवं किस्मों को चिन्हित किये जाने के साथ मुख्य शोध बिन्दुओं का क्रमवार चर्चा हुई इसमें राई–सरसों बीमारियों, बीमारी की रोकथाम, राई में संकर किस्मों का उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, परम्परागत तकनीकी सुधार, आदि पर गहन विचार विमर्श हुआ।

निदेशालय के निदेशक डॉ. पी.के. राय ने सभी का धन्यवाद करते हुये राई सरसो के विकास के लिये कार्य करने का विश्वास दिलवाया।

R.N.I.Regd.No.:RAJHIN/2005/16223
Postal Regd.No.:JAIPURCITY/108/2019-21

IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO
हलधर टाइम्स
सी-17, पुरोहित जी का बास,
सरकारी मिडिल स्कूल के पास,
22 गोदाम, जयपुर-302006

कृषि, सहकारिता, पशुपालन व ग्रामीण विकास का अग्रणी साप्ताहिक समाचार पत्र

हलधर टाइम्स

www.haldhartimes.in

23 जिले सूखे की जद में | @ 3 | मूल्य : ₹ 5/- पृष्ठ : 8 | जयपुर | वर्ष-15, अंक-40 | 10 अगस्त - 16 अगस्त, 2020 | (वार्षिक मूल्य : ₹250/-)

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ

हलचल

55 नये पशुधन सहायकों को नियुक्ति

जयपुर। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पशुओ को रोगो से बचाने और पशुपालको को राहत पहुँचाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने 55 नये पशुधन सहायको को नियुक्ति दी है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि कोविड-19 के सं मण को देखते हुए सरकार प्रदेश की पशुपालन संस्थाओ को और सशक्त बना रही है। जिसके तहत 55 नये पशुधन सहायको को नियुक्ति यां दी गई है। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक भर्ती-2018 के तहत अब तक 2112 पशुधन सहायको को पशुपालन विभाग द्वारा नियुक्ति दी जा चुकी है।

टमाटर की खेती पर वेबिनार कल

नई दिल्ली। हार्टिकल्चर ट्रेनिंग संस्थान उचानी-करनाल के द्वारा संरक्षित संरचना में टमाटर की खेती विषयक एक दिवसीय वेबिनार कल आयोजित की जायेगी। वेबिनार को उद्यानिकी महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी सम्बोधित करेंगे। वेबिनार में संरक्षित विधि के तहत टमाटर फसल में शस्य क्रिया और अर्थशास्त्र, रोग-कीट प्रबंधन, टमाटर का आपूर्ति श्रृखंला और मूल्यवर्धन विषय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की जायेगी।

16 तक करें आवेदन

जयपुर। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ने एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन और एग्रीप्रेन्योर्स की आइडिया कार्य म के तहत एग्री स्टार्टअप प्रशिक्षण के लिए 16 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किये है। इस कार्य म के तहत दो माह का प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण संबंधी जानकारी संस्थान की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

पाठक बने पत्रकार

हलधर टाइम्स के पाठक खेती / पशुपालन से जुड़ी समस्या, फोटो, जानकारी व्हाट्सएप के इन नम्बरों पर भेजें।

9828165521
7976452840

www.haldhartimes.in

सरसों की चार नई किस्म सहित तोरिया के नई किस्म की पहचान

तिलहन में आत्मनिर्भरता का पंच

पीयूष शर्मा

जयपुर। खाद्य तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने देश के किसानों को सरसों और तोरिया के नई किस्मों की सौगात दी है। नवविकसित किस्म में सरसों की दो किस्म देरी से बुवाई के लिए उपयुक्त है। सरसों किस्म डीआरएमआरआईसी-16-38 और डीआरएमआर-2017-15 किस्मों की पहचान नवम्बर महीने में बुवाई के लिए की गई है। इससे धान उत्पादक किसान भी फसल की कटाई के बाद सरसों का उत्पादन लें सकेंगे। गौरतलब है कि इन दोनों किस्मों का विकास राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर (भरतपुर) के कृषि वैज्ञानिकों ने 'डवलपमेंट ऑफ लेट सोइंग' प्रोजेक्ट के तहत किया है। इन किस्मों के अलावा पूसा मस्टर्ड-32, गोभी सरसों किस्म एकेएमएस-8141 और तोरिया किस्म टीएस-38 की पहचान आईसीएआर, नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राई-सरसों अनुसंधान परियोजना की 27 वीं कार्यशाला में की गई है। इस तरह देश के सरसों उत्पादक राज्यों के साथ-साथ तिलहन उत्पादन में उम्मीद की किरण बनकर उभर रहे पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को भी नई किस्मों की बुवाई का मौका मिलेगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. पीके राय ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता था कि देश के धान उत्पादक राज्यों में किसान धान की कटाई लेट होने के चलते सरसों की बुवाई नहीं कर पाते थे। ऐसे किसानों के लिए देर से बुवाई योग्य सरसों की कोई किस्म उपलब्ध नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए निदेशालय के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2012 में देर से बुवाई योग्य सरसों किस्मों के विकास की ओर कदम बढ़ाया। करीब आठ साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिक किसानों को दो नई सरसों किस्म की सौगात देने में कामयाब हुए है। उन्होंने बताया कि सरसों किस्म डीआरएमआरआईसी-16-38 और डीआरएमआर-2017-15 किस्म की बुवाई 15 नवम्बर तक की जा सकती है। डीआरएमआरआईसी-16-38 किस्म का विकास कृषि वैज्ञानिक डॉ. कुंवर हरेन्द्र सिंह और डीआरएमआर-2017-15 किस्म का विकास डॉ. एसएस मीना ने किया है। जबकि, पूसा-32 का विकास आईएआरआई, नई दिल्ली, गोभी सरसों किस्म का विकास शिवालिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, कागंड़ा(हिमाचल प्रदेश) और तोरिया किस्म का विकास आसाम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। इस तरह देश के सरसों उत्पादक किसानों को पांच नई किस्मों का लाभ जल्द ही मिलेगा। गौरतलब है कि देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन को मंजूरी दी है। ताकि, खाद्य तेल आयात को घटाया जा सके। इस मिशन के तहत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन तकरीबन 100 लाख टन से बढ़ाकर 180 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तिलहन फसलों का रकबा अगले पांच साल में बढ़ाकर 300 लाख हैक्टयर से ज्यादा किया जाएगा। सरकार एक तरफ तिलहनों की उत्पादकता में 50 फीसदी वृद्धि करना चाहती है तो दूसरी तरफ खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में करीब तीन किलोग्राम की कमी करने का लक्ष्य है। देश में तिलहनों का कुल उत्पादन इस समय तकरीबन 300 लाख टन होता है । जिसे अगले पांच साल में बढ़ाकर करीब 480 लाख टन करने का लक्ष्य है। डॉ. राय ने बताया कि धान उत्पादक राज्यो में 11 मिलियन हैक्टयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई होती है। अमूमन धान की कटाई अक्टूबर माह में किसान करते है। इससे धान उत्पादक राज्यों के किसान सरसों की बुवाई नहीं कर पाते थे।

45 फीसदी उत्पादन प्रदेश में

गौरतलब है कि सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में नबंर वन है। सकल उत्पादन में 45-48 फीसदी की भागीदारी रखता है। रबी में 25-26 लाख हैक्टयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई प्रदेश में होती है और सालाना औसत उत्पादन 34-35 लाख एमटी के करीब है।

नवविकसित किस्मों की विशेषता

डीआरएमआरआईसी-16-38 किस्म:- इस किस्म की पहचान जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के लिए की गई है। यह किस्म सिंचिंत अवस्था में देर से बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसान 15 नवम्बर तक इस किस्म की बुवाई कर सकेंगे। यह किस्म 132 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 39.9 प्रतिशत और औसत उत्पादकता 1733 किलोग्राम प्रति हैक्टयर है। निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अशोक शर्मा ने बताया कि विकसित दोनों किस्मों की बुवाई समय पर करके किसान दूसरी प्रचलित किस्मों के जैसे ही प्रति हैक्टयर 25-30 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। खास बात यह है कि देर से बुवाई के चलते पाला और शीतलहर से होने वाले नुकसान से भी किसान बच सकेगा। साथ ही जनवरी-फरवरी के मध्य तापमान बढ़ौतरी की स्थिति में उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डीआरएमआर-2017-15

इस किस्म में डीआरएमआरआईसी-16-38 की तुलना में तेल की मात्रा ज्यादा है। इस किस्म के बीजों में 40.7 फीसदी तेल की मात्रा विद्यमान है। यह किस्म 131 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी प्रति हैक्टयर उत्पादकता 1788 किग्रा है। इस किस्म की पहचान डीआरएमआरआईसी-16-38 वाले राज्यों के लिए की गई है।

पूसा सरसों -32

इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया है। इस किस्म की पहचान उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तरप्रदेश, जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लिए की गई है। यह किस्म 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 38 प्रतिशत और प्रति हैक्टयर उत्पादकता 2713 किलोग्राम है। यह किस्म समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है।

तोरिया किस्म टीएस-38

इस किस्म का विकास आसाम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। इस किस्म की पहचान सिंचिंत अवस्था में समय पर बुवाई के लिए आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मनीपुर, मिजोरम, पं. बंगाल और उड़ीसा राज्य के लिए की गई है। यह किस्म 93 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 41.1 प्रतिशत और प्रति हैक्टयर उत्पादकता 1689 किलोग्राम प्रति हैक्टयर है।

गोभी सरसों एकेएमएस-8141

इस किस्म की पहचान हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू और पंजाब राज्य के लिए की गई है। यह किस्म 166 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 40.5 प्रतिशत है। यह किस्म सिंचिंत क्षेत्र में समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रति हैक्टयर उत्पादकता 1915 किलोग्राम है। इस किस्म का विकास शिवालिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, कागंड़ा (हिमाचल प्रदेश) के कृषि वैज्ञानिकों ने किया है।

उत्पादन के मुकाबले दोगुना तेल आयात

भारत हर साल तकरीबन 150 लाख टन खाद्य तेल का आयात करता है। जबकि ,घरेलू उत्पादन तकरीबन 70.80 लाख टन है। ऐसे में खाने के तेल के लिए भारत मुख्य रूप से आयात पर निर्भर रहता है। जिसके लिए काफी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। ऐसे में देश का आयात बिल कम करने के लिए तिलहनों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना लाजिमी है। खाद्य तेल का सालाना आयात बिल करीब 75,000 करोड़ रुपए है और सरकार को इससे आयात शुल्क के तौर पर 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता ऐसे

विशेषज्ञ बताते हैं कि देश की बढ़ती आबादी के साथ तेल खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन, आईसीएमआर के एक शोध में एक व्यक्ति को रोजाना 30 ग्राम तेल खाने की सलाह दी गई है। इसका अनुपालन करने पर एक व्यक्ति साल में करीब 11 किलो तेल खाएगा। जबकि, एनएएस की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति तेल की खपत 19.3 किलो है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने और प्रति व्यक्ति उपभोग में कटौती किए जाने पर अगले पांच साल में भारत खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है।

एक लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा लांच

पीएम मोदी ने दिया कृषि क्षेत्र को कोरोना पैकेज

नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने कोविड-19 के तहत घोषित राहत पैकेज जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा शुरू की है। साथ ही, पीएम-किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड रुपये जारी कर दिए है। गौरतलब है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस कोष का इस्तेमाल शीत भंडारगृह, कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे पर किया जाएगा।

दशक तक रहेगा प्रभावी

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि 10 सालों तक यानी 2029 तक है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन का कार्य भी होगा। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और एग्रीटेक खिलाडियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इस वर्ष 10,000 करोड़ रुपये

सरकार के द्वारा चार वर्षों में ऋण वितरित किया जाएगा। चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक साल में 30,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित होंगे। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ की सीमा तक सभी ऋणों पर सालाना तीन फीसदी की ब्याज छूट दी जाएगी। इसकी सुविधा अधिकतम सात वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

पैदा होंगे रोजगार के अवसर

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित और मॉनिटर किया जाएगा। यह ऋण के लिए आवेदन करने के लिए सभी योग्य संस्थाओं को सक्षम करेगा। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सतर्कता — कृषि मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

विदेशी बीज को लेकर अलर्ट पर प्रदेश के बीज निरीक्षक

जयपुर (कास)। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच विदेशों में भारतीय कृषि की कमर तोडने की साजिश रची जा रही है। साजिश के तहत विदेशों से बीज के पार्सल भेजे जा रहे है। विदेशों से आ रहे बीज के बेनाम पार्सल को देखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने कृषि विभाग सहित प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय को अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्रालय के दिशा-निर्देश मिलने के साथ ही कृषि आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी बीज निरीक्षकों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (आदान) डॉ. रामगोपाल शर्मा ने बताया कि कृषि मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों में विदेशों से बीज के पार्सल आए है। जो भारत सरकार के नियमों के विरूद्ध है। इसको लेकर मंत्रालय के उप आयुक्त डॉ दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध बीज पार्सल देश की जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर सकते है।

फाईल फोटो

नहीं खोले बीज पार्सल

डॉ श्रीवास्तव ने कहा है कि बीज पार्सल की वास्तविक स्थिति से अवगत होने के बाद ही उसे खोला जाये। इसके बाद ही बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसानों को भी सलाह दी है कि वह सतर्क रहें और खेतों में बीज की बुवाई से पूर्व इसकी जांच जरूर कर लें। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय ने कृषि विभाग के साथ-साथ प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य बीज निगम और बीज प्रमाणीकरण संस्था को भी अर्लट जारी किया है।

कई देशों में भेजे गये संदिग्ध पार्सल

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों से ऐसी सूचना मिल रही है कि पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में ऐसे हजारों संदिग्ध बीज के पार्सल भेजे गये हैं। इसकी जांच में पुष्टि हुई है। डॉ श्रीवास्तव ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने इस मामले को ब्रशिंग घोटाला और कृषि तस्करी बताया है। इस अनचाहे बीज पार्सल में विदेशी आ ामक प्रजाति के बीज होने की आशंका जतायी गई है। जिनसे बीमारी पैदा करने के प्रयास की आशंका है। यह किसी भी देश के पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

पीएम को पत्र लिखकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह

टिड्डी से रबी में एक हजार करोड़ का नुकसान- गहलोत

जयपुर। प्रदेश में टिड्डी का कहर रबी-खरीफ फसल पर ही नहीं हो रहा है। बल्कि, राज्य का अर्थतंत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। टिड्डी नियंत्रण के लिए तमाम नियंत्रण के उपाय किए जाने के बावजूद भी वर्ष 2019-20 में 12 जिलों में करीब 6.70 लाख हैक्टयर क्षेत्र में रबी फसल को नुकसान हुआ है। इससे करीब एक हजार करोड़ के आर्थिक नुकसान का आंकलन राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में भी प्रदेश में अब तक करीब 3.83 लाख हैक्टयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया जा चुका है। लेकिन, टिड्डी का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। अण्डो से निकलने वाले फाका किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हुए है। सीएम गहलोत ने कहा है कि विश्व खाद्य कृषि संगठन के पूर्व अनुमानों के मुताबिक इस वर्ष राज्य में टिड्डी का प्रकोप पहले की तुलना में काफी ज्यादा होने की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार समय रहते उचित कदम उठाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल 11 अप्रेल को टिड्डियों ने राज्य में प्रवेश किया था। करीब 32 जिले टिड्डी से प्रभावित है। प्रदेश के साथ-साथ गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में भी टिड्डियों का प्रकोप हुआ है। अब टिड्डी बहुराज्यीय समस्या बन चुकी है। देश में इतने बड़े पैमाने पर टिड्डी का प्रकोप कई दशकों बाद देखा गया है। ऐसे में इस समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना सभी राज्यों के हित में होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय जरूरी

गहलोत ने पत्र में कहा है कि टिड्डी प्रकोप एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। नए टिड्डी दलों की उत्पति पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें उनके उद्गम स्थलों पर ही रोकना आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कर टिड्डी से प्रभावित सभी देशों के साथ बातचीत करे, ताकि टिड्डी के प्रभावी नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

फसल खराबे का लिया जायजा

उधर, हनुमानगढ जिला प्रभारी पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने नोहर क्षेत्र के गांव लालपुरा, किकरवाली और असरजाना के बीच टिड्डी प्रकोप से फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी संख्या में टिड्डी अंडे देती है अगर उसी स्थान पर टिड्डियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिले में काफी कम संख्या में टिड्डी आ पाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला परिषद के सीईओ परशुराम धानका और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि गोल्डलाइन
16 से 31 अगस्त, 2020 (पाक्षिक)
वर्ष : 13, अंक : 2, पेज : 5

देश के लिए तिलहन क्रांति में होगा बड़ा योगदान- डॉ. राय

राई-सरसों की पांच नई उन्नत किस्में विकसित

डॉ. अशोक कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट

सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर के नेतृत्व में अखिल भारतीय राई-सरसों परियोजना के अर्न्तगत देश में कार्यरत विभिन्न केन्द्रों द्वारा राई-सरसों की पांच किस्मों को विकसित किया गया है। इन्हें हाल में ही आयोजित अखिल भारतीय राई-सरसों अनुसंधान परियोजना की 27 वीं कार्यशाला में देश की विभिन्न जलवायु की परिस्थितियों के लिए अनुशंसित किया गया है। निदेशक डॉ. पी.के. राय ने बताया कि देश में खाद्य तेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है, इसलिए तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। राई-सरसों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाकर ही खाद्य तेलों मे बढ़ोत्तरी की जा सकती है। किसी भी फसल के उत्पादन में सही किस्मों का चुनाव महत्वपूर्ण है। देश के धान उत्पादक राज्यों में किसान धान की कटाई मे देर होने के चलते सरसों की बुवाई नहीं कर पाते थे। ऐसे किसानों के लिए देर से बुवाई योग्य सरसों की किस्म का विशेष महत्व है। इस स्थिति को देखते हुए निदेशालय के वैज्ञानिकों ने देर से बुवाई योग्य सरसों किस्मों के विकास पर जोर दिया और देरी से बुवाई के लिए उपयुक्त दो नई किस्मों को विकसित करनें में सफलता प्राप्त की।

सरसों की डी.आर.एम.आर.-2017-15 और डी.आर.एम.आर.आई.सी-16-38 किस्मों की पहचान जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के लिए की गई है। ये किस्में सिंचित अवस्था में देर से बुवाई के लिए उपयुक्त हैं। किसान 15 नवम्बर तक इन किस्मों की बुवाई कर सकेंगे। इससे धान उत्पादक किसान भी फसल की कटाई के बाद सरसों का उत्पादन लें सकेंगे। इसके अतिरिक्त समय से बुवाई के लिए पूसा-32 किस्म की पहचान की गई है। साथ ही गोभी सरसों की एके.एम.एस.-8141 एवं तोरिया की टी.एस-38 किस्मों को भी किसानों के लिए जारी किया गया है।

नवविकसित किस्मों की विशेषता

■ **डी.आर.एम.आर.-2017-15:-** यह किस्म 131 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 40.7 प्रतिशत और औसत उत्पादकता 1788 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इस किस्म को राधिका नाम भी दिया गया है। निदेशालय के वैज्ञानिक डॉ. एच. एस. मीना द्वारा विकसित किया गया है ।

■ **डी.आर.एम.आर.आई.सी.-16-38 किस्मः-** यह किस्म 132 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 39.9 प्रतिशत और औसत उत्पादकता 1733 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इस किस्म को बृजराज नाम भी दिया गया है। निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. कुंवर हरेन्द्र सिंह द्वारा विकसित किया गया है।

■ **पूसा सरसों-32:-** इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया है। इस किस्म की पहचान उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तरप्रदेष, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लिए की गई है। यह किस्म 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 38 प्रतिशत और प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 2713 किलोग्राम है। यह किस्म समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है।

■ **तोरिया की टी.एस-38 किस्मः-** इस किस्म का विकास आसाम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। इस किस्म की पहचान सिंचित अवस्था में समय पर बुवाई के लिए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणीपुर, मिजोरम, पं. बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए की गई है। यह किस्म 93 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 41.1 प्रतिशत और उत्पादकता 1689 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है।

■ **गोभी सरसों की एके.एम.एस.-8141:-** इस किस्म की पहचान हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू और पंजाब राज्य के लिए की गई है। यह किस्म 166 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 40.5 प्रतिशत है। यह किस्म सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 1915 किलोग्राम है। इस किस्म का विकास शिवालिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, कागंडा (हिमाचल प्रदेश) के कृषि वैज्ञानिकों ने किया है।